प्रशासनिक कसावट... प्रिंटिंग प्रेस पर पत्रिका पर लग जाएगा वैक्सीन का नोट, शहर में 75% लोगों को लग चुके दोनों टीके, 100% के लिए शादियों का सीजन... बड़ा टारगेट

अच्छी पहल : शादी में यह व्यंजन नहीं... वैक्सीन का स्टॉल है, मेहमानों को लगाए टीके, अब हर पत्रिका में लिखा दिखेगा वैक्सीन जरूर लगवाएं

नारायणी पैलेस में लगी वैक्सीन की स्टॉल, लोगों का उत्साह दिखा

रतलाम | जी हां, शादी की यह तस्वीर विशेष है। दरअसल, आप जो देख रहे हैं, वह रिसेप्शन में किसी व्यंजन की नहीं वैक्सीन का स्टॉल है। रविवार को नारायणी पैलेस में गजेंद्र बैरागी और डॉ. विजया वैष्णव की शादी हुई, उसमें यह नजारा दिखा। शादी में आने वाले मेहमानों ने उत्साह से भोजन के बाद वैक्सीन लगवाई। शहर प्रभारी लोकेश वैष्णव ने बताया शुरुआत दो घंटे में ही 17 से ज्यादा लोगों को टीके लग चुके थे, जो कि अच्छा है।

कलेक्टर के प्रिंटिंग प्रेस को आदेश, पत्रिका पर छपेगी अपील

यह फोटो शादी की पत्रिका है। इसपर टीका लगवाने की अपील है। करमदी विकास समिति के जितेंद्र राव की 23 नवंबर को होने वाली शादी में यह अपील की है। अब आपको हर पत्रिका पर ऐसी अपील दिखेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर एसडीएम अभिषेक गहलोत ने प्रिंटिंग प्रेस एसोसिएशन के अध्यक्ष को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि सभी प्रिंटिंग प्रेस सदस्यों को सूचित करें कि वे अपनी प्रिंटिंग प्रेस में छपाई के दौरान वैवाहिक, मांगलिक कार्यक्रमों की पत्रिकाओं पर नोट प्रिंट कराएं कि कार्यक्रम में ऐसे ही व्यक्ति शामिल हो, जिन्होंने कोविड-19 के टीके के दोनों डोज लगवा लिए हो।

सड़क पर निकलेगी टीम, आमजन को ढूंढ-ढूंढकर लगाएंगे टीके

यह तस्वीर बाजार क्षेत्र की है। जहां एक दिन पहले अधिकारियों की टीम वैक्सीन नहीं लगवाने वालों को ढूंढने निकली। मोबाइल नंबर पूछकर वेरिफिकेशन किया, जिन्होंने टीके नहीं लगाए थे, उन्हें तत्काल वैक्सीन लगाई गई। पेट्रोल पंप पर भी टीके लगे। अधिकारी आगे भी इस तरह टीके लगाएंगे। भास्कर

दै. भास्कर 15/11/21

एक ने बिना परमिशन सीसी रोड बनाकर काटे कॉटेज, दूसरे कॉलोनाइजर ने मुख्य प्रवेश मार्ग बता बेच डाले सारे कॉटेज

भास्कर संवाददाता | रतलाम

कनेरी और धोलावड़ रोड के बाद सरकारी अमले की नजर सागोद रोड पर भूमाफिया द्वारा सारे नियमों को ताक में रखकर काटी जा रही कॉलोनियों पर है। ऐसे ही एक संस्था मेसर्स पार्श्वनाथ डेवलपर्स और उसके भागीदार पवन पिता, पारसमल पिरोदिया, किरण पति कमल पिरोदिया, महेंद्र पिता बसंतीलाल पिरोदिया व अन्य को प्रशासन की कॉलोनी सेल ने दूसरी बार नोटिस जारी किया है। इन्होंने अवैध रूप से बगैर सक्षम स्वीकृति के बाजना फोरलेन से जोड़कर अंदर की तरफ लगभग 650 मीटर की सीमेंट कांक्रीट की रोड बना डाली। वहीं कॉटेज नूमा बड़े भूखंड काटकर बेच दिए। इतना ही नहीं इसका फायदा उठाते हुए पास वाली जमीन के मालिक भी कारस्तानी दिखाने से बाज नहीं आया। उसने टीएंडसीपी से पास ले-आउट के विपरीत बनाई सड़क को मुख्य प्रवेश मार्ग बताते हुए कॉलोनी बेच डाली। इसका नाम सैफरॉन बताया जा रहा है। पार्श्वनाथ डेवलपर्स को नोटिस जारी करने के बाद प्रशासन तक इस कॉलोनी की शिकायत पहुंच गई है। प्रशासन ने रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया सूचना के आधार पर संबंधित फर्म और भागीदारों को रिकॉर्ड दिखाने के लिए नोटिस जारी किए हैं। कॉलोनियों की शिकायत मिली है। ।

सड़क व कॉटेज को लेकर कॉलोनी सेल ने मांगे दस्तावेज

बिना सक्षम स्वीकृत के बनाई गई सीसी सड़क, इसी पर आगे कई कॉटेज बन चुके हैं।

दरअसल प्रशासन को ग्राम खेतलपुर स्थित सर्वे नंबर 34/17, 34/18 में स्थित सर्वे नंबर 34/24, 1/8, 1/9, 1/10, 1/1 और 7/1/1 भूमि पर अवैध रूप से बगैर सक्षम स्वीकृति के सीसी सड़क बनाकर कॉलोनी विकसित करने की शिकायत मिली थी। कलेक्टर कार्यालय की कॉलोनी सेल ने पार्श्वनाथ डेवलपर्स को नोटिस दिया था, जवाब नहीं देने पर कॉलोनी सेल ने 9 नवंबर को दूसरी बार नोटिस जारी कर तीन दिन में कॉलोनी से संबंधित दस्तावेज और अनुमतियां सहित 11 दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा है। समय सीमा गुजर गई है। सड़क पर बुलडोजर चल सकता है।

द्वारका रेजीडेंसी मामले में सुनवाई आज होगी

सैलाना रोड पर राम मंदिर के सामने ढाई महीने से अधूरी द्वारका रेजीडेंसी मामले में 15 नवंबर को कोर्ट में सुनवाई होगी। फर्म द्वारा लगाई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 15 नवंबर तक प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने की राहत दे दी थी। इन सब के बीच प्रशासन ने पूरी जमीन को वापस लेने की प्रोसेस शुरू कर दी है। बता दें कि शिकायत मिलने पर 29 अगस्त को नगर निगम व राजस्व अमले ने सरकारी जमीन को लोहे की जाली लगाकर सुरक्षित कर लिया था, वहीं कुछ दिन बाद सीसी वर्क को उखाड़ दिया था।

दै. भास्कर 15/11/21

पार्श्वनाथ डेवलपर को नोटिस जारी, दो साल पहले भी हुआ था

बिबड़ौद रोड की अवैध कालोनियों पर कार्रवाई की तैयारी

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। कृषि भूमि पर काटेज के नाम पर अवैध कालोनी काटने को लेकर चल रही कार्रवाई में अब बिबड़ौद रोड स्थित काटेजों को लेकर नोटिस जारी किए गए हैं। जयंतसेन धाम के समीप काटेज बनाए जाने पर कालोनी सेल से नौ नवंबर को जारी नोटिस में डेवलपर से तामिली के तीन दिन में जवाब मांगा गया है। इधर नगर निगम भी अनुमति विपरीत बने भवनों में कंपाउंडिंग के लिए मंगलवार से अभियान शुरू करेगा।

मालूम हो कि शहर के करमदी रोड, कनेरी रोड, सेजावता-बंजली बायपास, नंदलई रोड, ईसरथूनी रोड, डेलनपुर, ईटावा माताजी रोड सहित अन्य प्रमुख मार्गों पर गत पांच वर्षों में काटेजों के नाम पर 5500 वर्गफीट से लेकर 10 से 20 हजार वर्गफीट तक भूखंड बेचे गए। इससे अवैध बसाहट बढ़ने लगी है और शासन को राजस्व का नुकसान भी पहुंच रहा है। अब ऐसी कालोनियों में निर्माण तोड़े जा रहे हैं।

कनेरी रोड, धोलावड़ रोड पर तीन कालोनियों के निर्माण तोड़ने के बाद अब बिबड़ौद रोड पर कार्रवाई की तैयारी है। कालोनी सेल से किरण पत्नी कमल कुमार पिरोदिया, महेंद्र कुमार बसंतीलाल पिरोदिया, मै. पार्श्वनाथ डेवलपर्स भागीदार पवन पुत्र पारसमल पिरोदिया व अन्य को कालोनी सेल से नौ नवंबर को जारी नोटिस में ग्राम खेतलपुर स्थित सर्वे क्रमांक 34/17, 34/18, 34/24, 1/8, 1/9, 1/10, 1/1 पर अवैध कालोनी (काटेज) विकसित किए जाने को लेकर तीन दिन में कालोनी स्वीकृति के दस्तावेज, टीएनसीपी व नगर निगम से अनुमति, डायवर्जन सहित रेरा व अन्य अनुमति की जानकारी मांगी गई है। दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर अवैध निर्माण तोड़ने के साथ ही एफआइआर कराने की चेतावनी भी दी गई है।

दो साल में तीसरी बार मिला नोटिस

पार्श्वनाथ डेवलपर्स को दो साल में तीसरी बार नोटिस मिला है। इससे पहले जनवरी 2020 में नोटिस दिया गया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई और बाद में इस नोटिस से संबंधित फाइल भी नहीं मिली। इसके बाद आठ अक्टूबर 2021 व नौ नवंबर को नोटिस जारी किए गए। इसी भूमि से लगती अन्य बड़ी कालोनी में भी नियमित विपरीत निर्माण को लेकर कार्रवाई की तैयारी है। यहां का हिस्सा बिबड़ौद ग्राम पंचायत में आने से निर्माण अनुमति पंचायत से ली गई और टीएनसीपी से स्वीकृत नक्शे में भी हेरफेर किया गया है।

द्वारका रेसीडेंसी में आज

हाइकोर्ट में होगी सुनवाई : सैलाना रोड ओवरब्रिज के समीप बनी द्वारका रेसीडेंसी के आगे की शासकीय भूमि पर बेरिकेडिंग, रेसीडेंसी की निर्माण अनुमति, नक्शा व नजूल एनओसी निरस्त किए जाने के मामले में हाइकोर्ट में बिल्डर जितेंद्र नागल द्वारा लगाई गई याचिका पर आज सुनवाई होगी। इससे पहले 28 अक्टूबर को हाइकोर्ट ने प्रशासन को जवाब पेश करने के लिए समय देते हुए 15 नवंबर तक निर्माण अनुमति, शासकीय भूमि पर बेरिकेडिंग के आदेश के अमल पर रोक लगाई थी।

> जहां नियमानुसार कंपाउंडिंग हो सकती है, वहां नियमितीकरण का अवसर दिया जाएगा। अगर नियम में नहीं होगा और निर्माण या कालोनी अवैध पाई जाती है तो कार्रवाई होगी।
>
> - कुमार पुरुषोत्तम, कलेक्टर

नईदुनिया 15/11/21

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन: पिछड़े लोग स्व सहायता समूहों के जरिए हो रहे सशक्त

सबसे ज्यादा आदिवासी समूह मध्यप्रदेश में

पत्रिका खबर खास

गोविंद अग्निहोत्री
patrika.com

भोपाल. विकास की मुख्यधारा से पिछड़े लोग अब आगे आ रहे हैं। गरीब सक्षम हो रहे हैं। महिलाएं आर्थिक आजादी महसूस कर रही हैं। वंचित, शोषित आदिवासी वर्ग अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। यह सब हो रहा है दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए। इसके तहत स्व सहायता समूह बनाकर लोग सक्षम हो रहे हैं। दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। देश में 72.78 लाख से ज्यादा समूह कार्य कर रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा 124574 आदिवासी स्व सहायता समूह मध्यप्रदेश में हैं। ज्यादातर समूह महिलाओं के हैं।

राज्यों में स्व सहायता समूह

टॉप फाइव जिले

जिला	एसटी	कुल
झाबुआ	10161	10297
धार	10006	12935
बड़वानी	7533	8860
शहडोल	7384	11451
आलीराजपुर	7223	7303

विभिन्न क्षेत्रों में यह काम कर रहे समूह

छोटी-छोटी बचत और सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त कर स्व सहायता समूह विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय हैं। चूल्हे-चौके में उलझी रहने वाली महिलाएं अब बिजली मीटर रीडिंग कर रही हैं, स्कूली बच्चों की यूनिफॉर्म सिल रही हैं तो ऑक्सीजन प्लांट का भी संचालन कर रही हैं। इसके अलावा खेती-किसानी के कार्य, मिल्क प्रोडक्ट, हर्बल गुलाल, खिलौने, वन उत्पाद, सिलाई-कढ़ाई, राशन दुकान संचालन, मास्क निर्माण, अगरबत्ती, मोमबत्ती, बांस के उत्पाद, खाद्य सामग्री जैसे- चिप्स, पापड़, बड़ी का निर्माण समूह कर रहे हैं। साथ ही पोषण आहार का काम समूहों को देने की प्रक्रिया जारी है।

कोरोनाकाल में रोजगार छिना तो स्वयं की मिल कर ली स्थापित

बालाघाट जिले के चिचगांव की महिलाएं जिस राइस मिल में काम करती थीं, वहां से कोरोना काल में काम छिन गया था। ऐसे में महिलाओं ने स्व सहायता समूह 'योग्यता' बनाया। आर्थिक मदद मिली तो उसी मिल की मशीन खरीदकर अपनी मिल स्थापित कर ली। यह मशीन अध्यक्ष मीना राहंगडाले के घर मवेशी बांधने की जगह पर लगाई गई। समूह का जिक्र पीएम मोदी ने मन की बात में जनवरी में किया था।

राजस्व वसूली की मिली कमान

उमरिया जिले के आदिवासी बाहुल्य पाली विकासखण्ड के चौरी ग्राम में स्व सहायता समूह की महिलाओं को गांव के हाट बाजार के प्रबंधन, राजस्व वसूली की जिम्मेदारी पिछले महीने दी गई है। यह प्रारंभिक प्रयोग सफल रहने पर पूरे जिले के ग्रामीण इलाकों में हाट बाजार की जिम्मेदारी महिला स्व सहायता समूहों को दी जाएगी।

धार की धरा साड़ियों को अंतरराष्ट्रीय पहचान

धार की आदिवासी महिलाओं द्वारा बनाई जा रही साड़ियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से ऑर्डर मिल रहे हैं। मांडू रोड स्थित केंद्र पर धरा उत्पादन समूह की महिलाओं द्वारा कॉटन, चंदेरी और महेश्वरी साड़ियों को ब्लॉक प्रिंट से सजाकर तैयार किया जा रहा है। समूह की साड़ियां हैदराबाद, बेंगलुरू, विशाखापट्टनम, ऊटी, भोपाल, जबलपुर, चंडीगढ़, सिंगापुर, आस्ट्रेलिया में ऑन डिमांड बेची जा,रही हैं। एक और खास बात ये है कि सीता वसुनिया कारीगर की बनाई साड़ी को इटली की इंटरनेशनल फैशन मैग्जीन वोग के कवर पेज पर जगह मिल चुकी है।

पत्रिका

पत्रिका 15/11/21

स्वच्छ सर्वेक्षण • 2020 में मिली थी 49वीं रैंक, 20 नवंबर को आएगा 2021 का रिजल्ट, पिछड़ सकता है शहर

6000 अंक के सर्वेक्षण में 4700 का दावा, संभावना 3550 की ही

3 कारणों से रैंकिंग बिगड़ने का है डर

1. दिखावा ज्यादा, काम कम
2. आंकड़ों जैसी सफाई नहीं हुई
3. लोग नहीं जुड़े, फीडबैक कमजोर

भास्कर संवाददाता | रतलाम

सफाई की सालाना परीक्षा 2021 में हमारे शहर की रैंकिंग बिगड़ सकती है। 6000 अंक के स्वच्छ सर्वेक्षण में से निगम अफसर 4700 अंक मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, अप्रैल-मई में गुपचुप सर्वे के अनुसार आशंका 3550 से 3800 अंक मिलने की है। यह सच साबित हुई तो रैंकिंग 60 पार जा सकती है। ऐसा हुआ तो फील्ड में काम नहीं होना, कम्प्यूटराइज्ड डाक्यूमेंटेशन के अनुसार क्यूसीआई द्वारा किए सर्वे में सफाई नहीं मिलना और कमजोर सिटीजन फीडबैक कारण होंगे।

परिणाम 20 नवंबर को घोषित होंगे, अंक और रैंकिंग को लेकर अफसरों ने कयास लगाना शुरू कर दिए हैं। निगम का दावा सही रहा तो हमारा शहर इस बार टॉप 40 में आ सकता है। 2020 के स्वच्छता सर्वेक्षण में शहर को 49वीं रैंक मिली थी।

जानिए, स्वच्छ सर्वेक्षण में नगर निगम द्वारा प्रस्तुत किया गया दावा और उसकी वास्तविकता

वर्ग - सर्विस लेवल प्रोग्रेस

निर्धारित अंक	2400
निगम का दावा	1800-1900
संभावना	1500

- **निगम के जतन** - सारे मापदंड पूरे करते हुए तीन तिमाही डाटा व अन्य डाक्यूमेंट समय पर लोड करके कई दावे कर दिए।
- **कमजोरी** - कचरे का निष्पादन नहीं हो रहा, जबकि यह प्राथमिकता वाला मापदंड है। सेग्रिगेशन भी ठीक से नहीं हो पा रहा। निगम ठोस कदम भी नहीं उठा पाया।

वर्ग - सर्टिफिकेशन

निर्धारित अंक	1800
निगम का दावा	1200-1300
संभावना	850-950

- **निगम के जतन** - ओडीएफ डबल प्लस का सर्टिफिकेशन मिल चुका, अब गार्बेज फ्री सिटी 5 स्टार रेटिंग के लिए दावा।
- **मैदानी स्थिति** - 2020 में जीएफसी में शून्य रेटिंग मिली थी, बावजूद इसके निगम ने 5 स्टार का दावा कर रखा है, जो मिलना मुश्किल, सर्वे के अनुसार वन या टू स्टार रेटिंग मिल सकती है।

वर्ग - सिटीजन वाइस

निर्धारित अंक	1800
निगम का दावा	1400-1500
संभावना	1200

- **निगम के जतन** - वोट फॉर सिटी एप, 1969 हेल्पलाइन, एसएस 2021 पोर्टल, स्वच्छता एप का फीडबैक से 1.08 लाख से ज्यादा का फीडबैक लिया।
- **स्थिति** - पिछले साल नगर निगम ने फीडबैक करवाया था, इसलिए अच्छा रहा, इस बार ऐसा नहीं हुआ, इसलिए प्रतिक्रिया कमजोर रही, 2020 में बेस्ट स्माल सिटी इन सिटीजन फीडबैक अवॉर्ड मिला था।

पांच सालों में शहर की रैंकिंग

साल	रैंक/शहर
2016	79/-
2017	48/500
2018	72/4203
2019	62/6000
2020	49/4242
2021	?

नगर निगम सालभर इन परेशानियों में उलझा रहा

- **महामारी** - दूसरी लहर के कारण अप्रैल, मई में लॉकडाउन में उलझा रहा, तैयारी ठीक से नहीं हो पाई। इसी बीच क्यूसीआई की टीम सर्वे करके चली गई।
- **ड्यूटी** - स्वच्छता अमले की ड्यूटी घर-घर दवाई वितरण, कंटेनमेंट जोन, ऑक्सीजन सप्लाई में लगी रही, जिससे फिल्ड में ध्यान नहीं दे पाए।
- **एक्सपर्ट** - सर्वेक्षण में मदद के लिए सरकार द्वारा भेजे केपीएमजी कंपनी के एक्सपर्ट प्रतीक मिश्रा ठीक गाइडेंस नहीं दे पाए। अफसर उनके भरोसे बैठे रहे।
- **लापरवाही** - निगम आयुक्त और कुछ इंजीनियरों के अलावा बाकी के अफसर मैदानी में नहीं दिखे, जिनकी ड्यूटी लगाई उन्होंने ठीक से काम नहीं किया।

भास्कर

आगे क्या : 2022 के सर्वेक्षण की तैयारी शुरू

निगम ने 2022 के सर्वे की तैयारी शुरू कर दी है। एमआईएस व अन्य दस्तावेजों का कम्प्यूटराइजेशन शुरू हो गया है। यह इस बार 7500 अंक का होगा। 3000 अंक सर्विस लेवल प्रोग्रेस के, 2250 अंक सिटीजन वॉयस के और 2250 सर्टिफिकेशन के हैं। सरकार हर वार्ड का जीआईएस (ग्लोबल इंफॉरमेशन सिस्टम) से डिजिटल नक्शे बनवा रही है। इसमें वार्ड में उपलब्ध सुविधाएं जैसे सुलभ कॉम्प्लेक्स, सामुदायिक टॉयलेट, निगम कार्यालय, पानी की टंकी, गार्डन, कचरा निष्पादन अंकित किए जा रहे हैं।

सीएम की घोषणा के 11 साल बीते, नहीं बना आडिटोरियम

तीन से 14 करोड़ हो गई लागत, रिडेंसिफिकेशन योजना में अटकी है शहर की सौगात

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। शहर को नए स्वरूप में लाने के लिए आंतरिक सड़कों को फोरलेन में बदल दिया गया, लेकिन बड़ी योजनाओं पर सालों से प्लानिंग ही हो रही है। आडिटोरियम, जिला अस्पताल का नया भवन, शासकीय आवास, नवीन कलेक्टोरेट की बी विंग और अन्य कई कार्य ऐसे हैं जो रिडेंसिफिकेशन योजना में प्रस्तावित हैं। खास बात यह है कि वर्ष 2017 में साधिकार समिति से प्रस्तावित गोल्ड पार्क (जैम्स व ज्वैलरी) को पीपीपी मोड में बनाए जाने के लिए तैयार की गई रिडेंसिफिकेशन योजना में आडिटोरियम सहित तीन योजनाओं पर सहमति मिल गई थी, लेकिन चार साल बाद भी अमल नहीं हुआ। इसके चलते आडिटोरियम की लागत भी 3 से बढ़कर 14 करोड़ हो गई है।

मालूम हो कि अब शहर में जिला जेल की रिडेंसिफिकेशन योजना में 119 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्यों की रुपरेखा तय की गई है। इसमें आडिटोरियम, मानव सेवा समिति कार्यालय से शहर सराय तक सड़क निर्माण, सैलाना रोड पर शासकीय आवास, बिबडौद में नया जेल भवन प्रस्तावित है। इन प्रस्तावों पर भी शासन से सहमति की प्रक्रिया फिर से होगी। अगर इस बार भी देरी हुई तो सौगातें सपना बन जाएंगी। इससे पहले गोल्ड पार्क की करीब 175 करोड़ की योजना में 22 अप्रैल 2017 को तत्कालीन कलेक्टर बी. चंद्रशेखर ने भोपाल में हुई साधिकार समिति की बैठक में बिंदुवार प्रजेंटेशन देकर योजना की आवश्यकता को समझाया था। प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्वीकृति के बाद भी काम आगे नहीं बढ़ा।

समझें रिडेंसिफिकेशन योजना को : रिडेंसिफिकेशन योजना में किसी भी शासकीय परिसर, भवन या भूमि को निजी एजेंसी के माध्यम से विकसित किया जाता है और बदले में उसे उस भवन, भूमि का एक निश्चित प्रतिशत का हिस्सा विक्रय अथवा व्यावसायिक उपयोग के लिए दिया जाता है। इस हिस्से का विक्रय कर निजी एजेंसी अपनी लागत व लाभ अर्जित करती है।

कभी जमीन तो कभी लागत में उलझती रही योजना : मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने वर्ष 2010 में आडिटोरियम निर्माण की घोषणा कर एक करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की थी। आडिटोरियम के लिए पहले लोकेंद्र भवन के सामने की जमीन तय की गई थी, लेकिन वहां आपत्ति आने के बाद लंबे समय तक मामला अटकता रहा। बाद में कामर्स कालेज खेल मैदान की जमीन में से एक हेक्टेयर जमीन आरक्षित की गई। इस जमीन की शासकीय कीमत तय होने के बाद नगर निगम ने 10 लाख रुपये जमा भी करा दिए थे, लेकिन शेष लागत को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर वर्ष 2017 में आरडीए को एजेंसी बनाया गया। 19 अगस्त 2015 को मुख्यमंत्री आडिटोरियम का शिलान्यास भी कर चुके हैं। नदे.

> गोल्ड पार्क की योजना में जिला अस्पताल का नया भवन शामिल है। इसे भव्य व बड़ा बनाने के लिए आडिटोरियम को जिला जेल की योजना में लिया गया है। दोनों योजनाओं पर हाउसिंग बोर्ड नोडल एजेंसी रहेगा। शासन स्तर से सैद्धांतिक सहमति के बाद प्रस्तावों को साधिकार समिति के समक्ष रखा जाएगा। जल्द ही प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
>
> **- कुमार पुरुषोत्तम, कलेक्टर, रतलाम**

1200 के प्रस्ताव पर 800 सीट की मिली थी स्वीकृति

मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने शहर में आडिटोरियम की घोषणा वर्ष 2010 में की थी। वर्ष 2017 की रिडेंसिफिकेशन योजना में 1200 सीट की क्षमता वाले आडिटोरियम की लागत करीब 10 करोड़ रुपये बताई गई। तब साधिकार समिति सदस्यों ने 1200 सीट को बहुत अधिक बताते हुए भोपाल में भी इतना बड़ा आडिटोरियम नहीं होने की बात कही। तत्कालीन कलेक्टर ने सभी तथ्यों से अवगत कराया तो बाद में समिति ने क्षमता 800 कर निर्माण पर सहमति दी थी। अब 1000 सीट की क्षमता का आडिटोरियम प्रस्तावित है, जिसकी लागत 14.25 करोड़ आंकी गई है।

नईदुनिया 15/11/21

आरएसएस ने शुरू की राजीव बस्ती में शाखा

बस्ती के स्वयं सेवकों ने किया सफाई मित्रों का सम्मान

फोटो-आरटी-1506 व 1507

रतलाम. शहर के जवाहर नगर क्षेत्र में राजीव बस्ती में आरएसएस ने शाखा की शुरुआत की है। इस दौरान बस्ती के स्वच्छता प्रहरियों का सम्मान पुष्पमाला से करके मिठाई खिलाई गई। इस दौरान मातृ शक्ति बड़ी संख्या में उपस्थित रही।

आयोजन में शाखा विकीर के बाद समस्त स्वच्छता प्रहरीयों का तिलक लगाकर पुष्पमाला से स्वागत किया गया तथा इसके साथ ही मिष्ठान का भी वितरण किया गया। सम्मान आयोजन में जिला संघचालक सुरेंद्र सुरेका भी उपस्थित रहे इस दौरान जिला संघचालक सुरेका ने कहा कि समाज का समाज में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कोई कार्य बड़ा या छोटा नहीं होता है। बल्कि हर मनुष्य अपने कार्य से बड़ा होता है। अगर सफाई मित्र स्वच्छता के प्रति जागृत रहकर कार्य नहीं करें तो शहर में गंदगी के चलते बीमारियां बढ़ जाएगी, इसलिए यह वर्ग सदैव आदर का पात्र है। हमको किसी बहकावे में नहीं आकर एकता रखना होगी व हिंदू समाज को संगठित रहना होगा। यह होगा तो ही समाज मजबूत होगा। इसके पूर्व स्वयं सेवकों ने शाखा में ध्वज प्रणाम आदि किया। आयोजन में क्षेत्रीय रहवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

पत्रिका

पत्रिका 15/11/21

स्वदेश

प्रदेश के हर एक जिले में उद्योगों का जाल बिछाया जाएगा- सकलेचा

कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को 143.36 करोड़ रुपए के ऋण वितरित

रतलाम ● स्वदेश समाचार
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के तत्वावधान में विधायक सभागृह पर क्रेडिट आउटरीच अभियान के तहत मेगा कैंप आयोजित हुआ। कैंप में शासन की कल्याणकारी योजनाओं के तहत हितग्राहियों को 143.36 करोड रुपए के ऋण विभिन्न बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए गए।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक चैतन्य काश्यप, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी तथा सीईओ एम.वी. राव, बैंक के फील्ड जनरल मैनेजर एस.डी. माहुरकर तथा कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम शामिल हुए। श्री सकलेचा ने कहा कि प्रदेश के हर एक जिले में सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगों का जाल बिछाया जाएगा, सबके सहयोग से मिलकर हम आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की दिशा में हम बढ़ रहे हैं। मंत्री श्री सकलेचा ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि कार्यक्रम में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सर्वोच्च अधिकारी एमडी तथा सीईओ एमवी राव भी उपस्थित हैं। श्री काश्यप ने कहा कि क्रेडिट आउटरीच जैसे कार्यक्रम यह दर्शा रहे हैं कि शासन द्वारा आमजन की भलाई के लिए उनके बीच जाकर कार्य किया जा रहा है। श्री राव ने कहा कि भारत सरकार ने बैंकों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कई विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ किए हैं। कोरोना काल में ठप्प हुए रोजगार से निर्मित स्थिति में बैंकों द्वारा प्रदत्त सेवाओं को सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम बताया। उन्होंने कहा एक कार्य योजना के तहत क्रेडिट आउटरीच जैसे कार्यक्रम प्रदेश के 52 जिलों तथा 313 ब्लॉक में आयोजित किए जा रहे हैं जिनके माध्यम से कोरोना के बाद की अर्थव्यवस्था को नई गति तथा पुनर्जीवन देना है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने ,सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के फील्ड जनरल मैनेजर एस.डी. माहुरकर ने भी संबोधित किया।

143 करोड रुपए से ज्यादा राशि के ऋण वितरित- मेगा कैंप में ऐतिहासिक रूप से 143.36 करोड़ रुपए के विभिन्न वर्गों को बैंकों द्वारा अतिथियों के हाथों वितरित कराए गए। जिले के 100 से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों को 7 करोड़ 87 लाख रूपए के ऋण प्रदान किए गए। इसी तरह सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के तहत 336 हितग्राहियों को 55 करोड़ 54 लाख रूपए के ऋण वितरण किए गए। रिटेल के तहत 99 हितग्राहियों को 49 करोड़ 92 लाख के, कृषि क्षेत्र के 606 हितग्राहियों को 21 करोड़ 81 लाख रुपए, के, पीएम मुद्रा में 131 हितग्राहियों को 5 करोड़ 60 लाख रुपए के, मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर में 66 हितग्राहियों को 12 लाख रुपए के ऋण वितरित किए गए।

स्वदेश 15/11/21

सभी टीके समय पर लगे तो ही बीमारी पर नियंत्रण संभव

रतलाम। डब्ल्यूएचओ के सौजन्य से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में डब्ल्यूएचओ के सर्विलेंस मेडिकल आफिसर डा. रितेश बजाज ने बताया कि पोलियो सहित मीजल्स, रूबेला डिप्थीरिया, परट्यूसिस और नियोनेटल टिटनस के मामलों पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा निगरानी रखी जाए एवं लक्षणयुक्त मरीजों का तत्काल जांच कर उपचार किया जाए। शिशु जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु तक बच्चों को सभी टीके निर्धारित समय पर लगाए जाना चाहिए। कार्यशाला के दौरान बीमारियों के चि-लक्षण, सैंपल लेने की प्रक्रिया आदि की जानकारी दी गई। कार्यशाला में जिला टीकाकरण अधिकारी डाक्टर वर्षा कुरील, डब्ल्यूएचओ के सहायक विवेक राठौर, डा. गौरव बोरीवाल, श्वेता बागड़ी, सरला वर्मा, नीलेश चौहान सहित सभी विकासखंड के बीएमओ, बीपीएम बीसीएम, बीईई तथा अन्य विभागीय अधिकारी, कर्मचारी आदि उपस्थित रहे।

अदुनीशा 15/11/21

अखिल भारतीय जागरुकता व पहुंच कार्यक्रम हुआ

अमृत महोत्सव में निकली रैली

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. आजादी का अमृत महोत्सव आयोजन के अंतर्गत अखिल भारतीय जागरुकता व पहुंच आयोजन चल रहा है। इसी के अंतर्गत जागरुकता लाने के लिए रविवार को बाल दिवस मनाया गया व रैली निकाली गई।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के अंतर्गत में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर मध्य प्रदेश के निर्देशानुसार मनाए जा रहे 45 दिवसीय अखिल भारतीय जागरूकता एवं पहुंच कार्यक्रम के अंतर्गत शहर में रैली निकाली गई। बाल दिवस के अवसर पर प्रधान जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजेश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में एडीआर सेंटर जिला न्यायालय से प्रभातफेरी व जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं द्वारा पेम्पलेट व बेनर के माध्यम से नालसा एवं सालसा के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विधिक सहायता योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया। विशेष न्यायाधीश डीएस चौहान, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय हितेंद्र मिश्रा तथा अभिभाषक संघ अध्यक्ष अभय शर्मा के द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। सीजीएम कपिल वर्मा, न्यायाधीश योगेंद्र त्यागी, शैलेंद्र बतकारिया, अफजल खान, लक्ष्मण वर्मा उपस्थित रहे।

पत्रिका 15/11/21

शहर में ऑडिटोरियम बनेगा, नवीन जिला जेल बिबड़ोद में बनाई जाएगी

जिला समिति द्वारा प्रारंभिक परियोजना प्रतिवेदन अनुमोदित

रतलाम ● स्वदेश समाचार

रीडेंसीफिकेशन योजना के तहत जिला समिति की बैठक कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

कलेक्टर कक्ष में आयोजित उक्त बैठक में रतलाम सहित जावरा तथा सैलाना मे रीडेंसीफिकेशन के तहत किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के प्रारंभिक परियोजना प्रतिवेदन अनुमोदित किए गए रतलाम शहर में 119 करोड रुपए के नवीन कार्य रीडेंसीफिकेशन योजना के तहत किए जाएंगे। बैठक में जिन प्रारंभिक परियोजना प्रतिवेदनों का अनुमोदन किया गया है वे सैद्धांतिक सहमति के लिए शासन को भेजे जा रहे हैं। इसके पश्चात डीपीआर बनेगी, निविदा पश्चात कार्य प्रारंभ होंगे। मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल मॉनिटरिंग एजेंसी रहेगा। प्रस्ताव के अनुसार सागोद रोड बिबड़ोद में नवीन जेल बनाई जाएगी। बताया गया कि वर्तमान जेल परिसर की 1.7038 हेक्टेयर भूमि वाणिज्य उपयोग में ली जाएगी। सागोद रोड बिबड़ोद में 30.40 हेक्टेयर भूमि का उपयोग करते हुए 6276 लाख रुपए लागत से नवीन जेल के मुख्य भवन, जेल विभाग के 76 आवासगृहों तथा परिसर के चारों ओर कंक्रीट की बाउंड्रीवाल बनेगी। एक और प्रस्ताव में रतलाम शहर के लिए 1425 लाख रुपए लागत से 1000 दर्शक क्षमता वाले ऑडिटोरियम निर्माण की प्रारंभिक परियोजना प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया। ऑडिटोरियम कामर्स कालेज के पीछे बनाया जाएगा। नागरिक विश्रांति गृह से शहर सराय तिराहे तक 325 लाख रुपए की लागत से सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण प्रस्ताव भी अनुमोदित किया गया शहर में राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए शासकीय आवासगृहों का निर्माण भी किया जाएगा जिनकी लागत 2356 लाख रुपए होगी। इनमें 10 ई-टाइप, 48 एफ टाइप तथा 48 जी टाइप क्वार्टर होंगे।

बैठक में सैलाना के विश्रामगृह की 0. 87 हेक्टेयर भूमि तथा परियोजना कार्यालय सैलाना की 0.50 हेक्टेयर भूमि का वाणिज्यिक उपयोग करने, सैलाना में अन्य स्थान पर 1968 लाख रुपए की लागत से नवीन विश्रामगृह, नवीन तहसील, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, प्रशासकीय संकुल तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए आवासगृहों के निर्माण प्रस्ताव भी अनुमोदित किए गए। बैठक में जिले की जावरा उप जेल परिसर के भवनों के जीर्ण शीर्ण होने, जेल गतिविधियों के लिए अपर्याप्त होने, सघन आवासीय ए वाणिज्य क्षेत्र में आ जाने रीजेसीफिकेशन की आवश्यक प्रतिपादित करते हुए उप जेल व भूमि वाणिज्य उपयोग में लेने त नवीन जेल परिसर ग्राम भूतेड़ा 5.50 हेक्टेयर मे निर्माण प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया संपूर्ण जेल परिसर तथा शासकी आवासों के निर्माण पर लगभ 22 करोड़ रुपए खर्च आएगा इसके अलावा जावरा में 30 दर्शक क्षमता वाले आडिटोरियम निर्माण के प्रस्ताव का भ अनुमोदन किया गया है जो करोड़ रुपए में बनेगा।

स्वदेश

स्वदेश 15/11/21

शादी की पत्रिका पर लिखा होगा दोनों डोज लगवाने वाले ही आए

पत्रिका
सिटी
हैपनिंग

प्रशासन ने प्रिंटिंग प्रेस एसोसिएशन रतलाम के अध्यक्ष को पत्र जारी कर दिए निर्देश

80 फीट रोड स्थित नारायणी पैलेस में वैष्णव परिवार के विवाह समारोह में वैक्सीनेशन शिविर भी आयोजित किया गया।

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. कोविड टीकाकरण को लेकर लोगों को जागृत करने के लिए प्रशासन ने अब नया हथकंडा अपनाया है। इसके चलते प्रशासन ने अब शादी की पत्रिकाओं पर विशेष टीप अंकित करने के संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं जिसके तहत प्रिंटिंग प्रेस वालों को सभी वैवाहिक कार्यक्रम की पत्रिका पर लिखना होगा कि शादी-समारोह में ऐसे ही व्यक्ति सम्मिलित हो जिन्होंने कोविड-19 के टीके के दोनों डोज लगवा लिए हो।

पत्रिका पर टीकाकरण से जुड़ी यह टीप अंकित किए जाने के पीछे उद्देश्य लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करना है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर एसडीएम अभिषेक गहलोत द्वारा प्रिंटिंग प्रेस एसोसिएशन रतलाम के अध्यक्ष को पत्र जारी कर निर्देशित किया गया है कि वैवाहिक पत्रिका पर टीकाकरण संबधित नोट अंकित करने के लिए अपने सदस्यों को सूचित करें। कोविड टीकाकरण में प्रत्येक व्यक्ति के दोनों डोज सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं।

यह दिए निर्देश

प्रिंटिंग प्रेस एसोसिएशन के अध्यक्ष को जारी पत्र में निर्देशित किया गया है कि उनके एसोसिएशन के अंतर्गत आने वाले समस्त प्रिंटिंग प्रेस सदस्यगणों को सूचित करें कि वे अपनी प्रिंटिंग प्रेस में छपाई के दौरान वैवाहिक, मांगलिक कार्यक्रमों की पत्रिकाओं पर नोट प्रिंट कराएं कि कार्यक्रम में ऐसे ह व्यक्ति शामिल हो जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीन के दोनों डोज लगव लिए हो।

वैश्विक महामारी के रूप में चिन्हित

दरअसल कोविड-19 बीमारी क डब्ल्यूएचओ द्वारा वैश्विक महामार के रूप में चिन्हित किया गया है तथ मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धार 50 के अंतर्गत संपूर्ण मध्यप्रदेश राज के लिए संक्रमण रोग घोषित किय है। रतलाम जिले में वर्तमान में बड़ संख्या में लोगों के द्वारा वैक्सीनेशन कराया गया है लेकिन कई लोग अ भी इसमें लापरवाही बरत रहे ह जिसके चलते प्रशासन को इस तर के निर्देश जारी करना पड़ रहे हैं।

पत्रिका 15/11/21